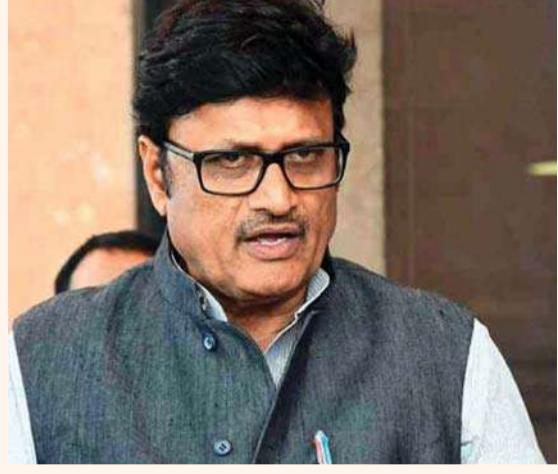


संघर्ष का दूसरा नाम "राजेंद्र" राठौड़, बन गए राजस्थान भाजपा के दबंग योद्धा

ऐसा प्रखर वक्ता जिसे सुनने के लिए सदन में भी विधायक रहते हैं उत्सुक, जिसकी जितनी संघर्ष की कठिन गाथा उसकी उतनी ही है बेमिसाल सफलता की गाथा

जयपुर टाइम्स



**राजस्थान विधानसभा में पार्टी के विधायकों को
एकजुट बनाए रखने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई**

जानकार लोगों का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ जब तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे तब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन के अंदर और सदन के बाहर एकजुट बनाए रखने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई, चाहे बीजेपी के विधायक विपक्ष की गैलरी में बैठे हो या फिर सत्ता पक्ष में हो राठौर ने हमेशा सदन में पार्टी का डाका बुलंद रखने के लिए विधायकों को एकजुट रखा, अगर बीजेपी को विपक्ष की भूमिका मिली तो उन्होंने सरकार को कैसे और किस तरह से घेरना है और किन मुद्दों को लेकर घेरना है इन सब की रणनीति तैयार करने में राठौर हमेशा आगे नजर आए भले ही उन्हें विपक्ष के नेता पद की भूमिका काफी विलंब से मिली हो लेकिन सदन में उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा के विधायकों को एकजुट रखा ताकि सत्ता पक्ष की ठीक तरह से घेराबंदी की जा सके, जब वसंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया विपक्ष के नेता रहा करते थे तब भी विधानसभा में पार्टी से जुड़े तमाम कामों की जिम्मेदारी राठौर ही संभाल करते थे राठौर की राय को ही सर्वोपरि माना जाता था और राठौर ही विधायकों से नियमित रूप से संपर्क में रहकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहते थे इसलिए राजस्थान विधानसभा में भाजपा की आवाज को बुलंद करने में राठौर हर तरह से हमेशा आगे रहे

राजनीतिक साजिश के तहत राठौर को दारिया एनकाउंटर मामले में फसाया गया लेकिन कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया

वर्ष 2006 में यजुपुर के राजेंद्र नगर में पुलिस की मुठभेड़ में शराब तस्कर दरिया की मौत हो गई थी बाद में दरिया की पत्ती ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और इस मामले में राजेंद्र राठौड़ को भी आरोपी बनाया गया, कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई ने भी अपनी जांच में राजेंद्र राठौड़ को दोषी माना और वर्ष 2012 में सीबीआई ने राजेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार किया उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तथा राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक थे हालांकि राठौर के समर्थकों ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राठौर की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है लेकिन राठौर ने अपने समर्थकों को संदेश दिया कि मैं निर्दोष हूँ और एक दिन सत्य की जीत होगी आप सब शांत रहें अपना काम करें बाद में 51 दिन तक राठौर जेल में भी रहे लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने उन्हें और इस मामले में सभी आरोपियों को निर्दोष कोर्ट के राजेंद्र राठौड़ को निर्दोष करार देने के बाद हर कोई कहने लगा कि यह एक उच्च स्तर पर राजनीतिक साजिश थी उस समय राजस्थान और केंद्र दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी ।

पार्टी से कभी भी नहीं की गद्दारी, हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहे राठौर

जिस दिन से राजद्र सिंह राठोड़ भाजपा में सामिल हुए उस दिन से ही राठोर पूरी तरह से भाजपा के प्रति समर्पण रहे, हालांकि इस दोरान भाजपा ने भी उन्हें ख्यूब मान सम्मान दिया और अच्छे पदों पर बिठाया भी लोकिन कुछ मार्क एस भी आए जब पार्टी के बड़े नेताओं का आपस की लड़ाई में राठोर को बेवजह बीच में घसीटा गया जिसकी वजह से उन्हें भी जहर का धूप पीना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी राजेंद्र राठोड़ ने पार्टी के संगठन को मज़बूत करने के प्रयासों में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और तब मन थन से पार्टी की सेवा करते रहे, विषपक्षीदलों के नेताओं की बयान बाजी को उन्हीं के अंदाज में राठोर ने पलट कर जवाब भी दिया, चाहे पार्टी के संगठन से जुड़ा मामला हो या फिर अपनी पार्टी की सरकार से जुड़ा कोई मामला हो जब भी पार्टी को राठोर की जरूरत महसूस हुई राठोर दौड़कर आए और पार्टी ने जो भी उन्हें जिम्मेवारी दी तु उस जिम्मेवारी को निभाया, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव हर चुनाव में पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी अब तक उस जिम्मेदारी को बख्खी से निभाया है, हमेशा पार्टी वेस्टर्न स्टार प्रचारक रहे और स्टार प्रचारक के दौरान भी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने में दिन-रात एक कर दिए इसीलिए राजेंद्र राठोर को काफी भाग दौड़ और मेहनत करने वाला नेता माना जाता है, राठोर ने कभी भी पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर काना नहीं किया हमेशा पार्टी के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही राजनीति की, पिछले लोकसभा चुनाव में राठोर को टिकट मिलने की चर्चा थी राठोर ने भी कह दिया था कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे हालांकि से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से मना भर कर दिया था लेकिन पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया उसके बाद भी राठोर ने किसी भी तरह की कोई नाराजगी प्रकट नहीं की और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की उम्मीदवारों को जीतने के लिए दिन-रात मेहनत की, यही वजह है कि राठोर को निष्ठावान पार्टी का नेता माना जाता है

राठोर का विरासत में नहीं मिला राजनीति, पिता
उत्तम सिंह राठोड़ थे आरएस अधिकारी

आज राजद्र सह राठौर को गिनता भाजपा के टाप नंतर आ में हाता है, राठौर ने सफ्ट अपने बूते पर कठिन संघर्ष और बुलंद हैसल्टों से राजस्थान की राजनीति में जो नाम कमाया है और भाजपा में खुद को साबित किया है वह अपने आप में बेमसाल है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को विरासत में राजनीति नहीं मिली थी और शुरू के दो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही उनकी जगह अगर और कोई राजनेता होता और शुरू के दो चुनाव हार जाता तो फिर शायद वह तीसरा चुनाव नहीं लड़ता लेकिन राठौर ने तीसरा चुनाव भी लड़ा और फिर चुनाव जीते और फिर लगातार सात बार चुनाव जीते इस दौरान झूठे मुकदमों में जेल में भी गए लेकिन टूटे नहीं अपने हैसल्टों को बुलंद रखा और सच्चाई पर चलते रहे। समय निकालकर राठौर बकालत भी करते हैं हालांकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजय मिलने के बाद राठौर के पास इस समय पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि या तो राठौर को आने वाले दिनों में कोई बड़ी राजनीतिक नियुक्ति मिल सकती है या फिर भाजपा की केंद्रीय की नई टीम में उन्हें बड़ी भूमिका में रखा जा सकता है।

अपनी पार्टी की सरकार में हर मुख्यमंत्री का दिल से दिया साथ

राजेंद्र सिंह राठौर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब-जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तब राजेंद्र राठौर ने हर मुख्यमंत्री का दिल से पूरा सपोर्ट किया, भैरव सिंह शेखावत सरकार में भी एक बार निर्दलीय विधायकों का समर्थन दिलवाने में राजेंद्र राठौर का बहुत बड़ा हाथ रहा था इसी तरह से वसुंधरा राजे पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी तो वसुंधरा राजे के दोनों शासनकाल में राजेंद्र राठौर कैविनेट मंत्री बने लेकिन सरकार से जुड़े हर विषयों को लेकर वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौर से चर्चा करके ही कोई निर्णय लेती थी, राजस्थान विधानसभा में अपनी सरकार का बचाव करने के लिए राजेंद्र राठौर काफी दृढ़ धूप और मेहनत किया करते थे राजस्थान विधानसभा में सरकार को नीचा नहीं देखना पड़े इसके लिए अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ भी विचार विमर्श करके उन्हें आवश्यक सलाह देते रहते थे उनके मन में यह भाव कभी भी नहीं आया कि मुझे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है वह हमेशा समर्पित भाव से अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के समर्थन में ढाल बनकर खड़े नजर आए और वर्तमान में भी प्रदेश की भजनलाल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हर तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं हालांकि अभी राठौर विधायक नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार से जुड़े लोगों के साथ जरूरी विषय पर बातचीत करते रहते हैं और अपनी सलाह और राय भी देते रहते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही राजेंद्र राठौर के बहुत अच्छे रिश्ते हैं।

मंत्री रहने के दौरान भी बड़े विभागों का कुशलता से किया संचालन, खुद को श्रेष्ठ मंत्री के रूप में साबित किया

वसुंधरा राजे के दोनों शासनकाल में राजेंद्र राठौड़ कैबिनेट मंत्री रहे और कई बड़े-बड़े विभागों की जिम्मेवारी राठौड़ को दी गई ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, चिकित्सा विभाग और संसदीय कार्य मंत्री जैसे कई बड़े विभाग उन्हें दिए गए और इन सभी विभागों में उन्होंने बहुत शानदार और बेमिसाल काम करके दिखाया कई बड़ी योजनाएं और कई बड़े-बड़े निर्णय लिए जिनकी वजह से विभागों के कामकाज की तो खूब तरीफ हुई इसके अलावा प्रदेश के लोगों को भी खूब फायदा हुआ, राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी उन्हें खूबी से थी जितनी गांव की समस्याओं के बारे में वे जानकारी रखते हैं उतनी ही बड़े शहरों की समस्याओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं इसीलिए जनता से जुड़े विषयों के बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी इसी वजह से राजस्थान विधानसभा के अंदर उनके जो भाषण हुआ करते थे वह काफी दमदार और तथ्यात्मक हुआ करते थे जिन्हें हर कोई सुनना पसंद करता था इसी वजह से राठौड़ जब राजस्थान विधानसभा में किसी भी विषय पर अपना भाषण देते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य चुपचाप उनकी बातों को सुना करते थे क्योंकि वे जो भी बात बोलते थे पूरी तैयारी के साथ रात भर स्टडी करके आते थे और पिर धारा प्रवाह हर विषय पर बारीकी से जानकारी दिया करते थे जिसकी वजह से उनकी बातों को हमेशा विधानसभा सचिवालय और सरकार दोनों काफी गंभीरता से लेती थी ।

भाजपा 14 अगस्त को मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 को चलेगा हर घर तिरंगा अभियानः मदन राठौड़

जयपुर टाइम्स



अपने प्राण, घर और सम्मान खोना पड़ा था। इस दिन पार्टी उन सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी जिन्होंने विभाजन की पीड़ा झेली और फिर से जीवन को खड़ा किया। राठौड़ ने कहा, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम देश की एकता, अखंडता और भार्दीचरे को बनाए रखेंगे।" उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर तिरंगा बांटेंगे और नागरिकों से राजनीति से ऊपर उठकर

राष्ट्रध्वज फहराने की अपील करेंगे। राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि "गहलोत जी बार-बार मानेसर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं विभाजन को याद कर भावुक हो जाता हूं, तो क्या सचिन पायलट उन्हें 'निकम्मा-नकारा' कहने की बात भूल पाएंगे?" उन्होंने कांग्रेस पर 'भगवा आतंकवाद' के नाम पर निर्दोषों को जेल में डालने और संघ के खिलाफ साजिशें रचने का

आरोप लगाया। मतदाता सूची की शुद्धता पर जो देते हुए राठौड़ ने कहा, "देश का नागरिक ही देश का भविष्य तय करे, यह जरूरी है। रीहंन्या, बांग्लादेशी या इटली से आया व्यक्ति भारत में वोट न डाल सके, इसके लिए मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण आवश्यक है।" उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ कार्य करती है और सभी वर्गों में सौहार्द बनाए रखने को संकल्पबद्ध है।

चिकित्सा शिक्षा को लगा पैसे का रोग



इस प्रकार चिकित्सा शिक्षा का अंधा विस्तार मात्र करके हम अपने यहां की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नहीं पा सकते। चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना वास्तव में एक भोथरी रणनीति ही कहा जाएगा। इस रणनीति पर चल कर आप इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच की खार्फ को नहीं पाट सकते और तब तो खासकर इस अंतराल को नहीं भरा जा सकता जब आप चिकित्सा शिक्षा को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के रहमोकरम पर छोड़ देते हैं। अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले निजी महाविद्यालय का शुल्क ढाँचा एक आम नागरिक के बच्चे की पहुंच से बहुत बाहर होता है। एक अंग्रेजी अखबार में छब्बीस अगस्त को छपी खबर के मुताबिक तमिलनाडु में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी संस्थानों का औसत शुल्क लगभग दो करोड़ तक पहुंच गया है। परस्नातक और अन्य प्रकार की चिकित्सा

जी क्षेत्र को चिकित्सा शिक्षा में उतरने की छूट देने के पीछे तर्क दिया गया कि सरकारी महाविद्यालय उतने चिकित्सक तैयार नहीं कर सकते, जितनी जरूरत है। दूसरे, प्रतिसर्पण बढ़ने पर शुल्क स्वतं कम हो जाएंगे। लेकिन चिकित्सा शिक्षा के निजी महाविद्यालयों की संख्या करीब पांच सौ तक पहुंच जाने पर भी क्या शुल्कों में बिशवट आई है?

भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की वस्तुरिथि जानने के लिए समय-समय पर जो आयोग और समितियाँ गठित की हैं, उन सबकी रिपोर्टों में समान रूप से बार-बार एक ही तथ्य उभर कर आता है कि बहुसंख्यक भारतीय समुचित और यथेष्ट स्वास्थ्य सेवाओं से वर्चित हैं। वर्तमान समय में देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर दोहरा बोझ है। एक तो आम जनता संकामक और मौसमी बीमारियों से सतत रूप से आक्रांत रहती ही है। दूसरे, पेशेवर चिकित्सकों की जमात शहरों में ही केंद्रित होती जा रही है। इन दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए जहां हमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि करनी होगी, वहीं पेशेवर चिकित्सकों का प्रशिक्षण इस प्रकार से करना होगा कि वे जहां हमारे देश की प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनें, वहीं मानसिक रूप से भी यह जिम्मेदारी उठाने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। ऐसा देखा गया है कि वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐसे स्नातक चिकित्सक तैयार नहीं कर पा रही जो गांवों और कस्बों में रह कर आम जनता की स्वास्थ्य विषयक तकलीफों का निदान कर सकें। इस प्रकार चिकित्सा शिक्षा का अंथा विस्तार मात्र करके हम अपने यहां की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नहीं पा सकते। चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना वास्तव में एक भोयरी रणनीति ही कहा जाएगा। इस रणनीति पर चल कर आप इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को नहीं पाठ सकते और तब तो खासकर इस अंतराल को नहीं भरा जा सकता जब आप चिकित्सा शिक्षा को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के रहमोकरम पर छोड़ देते हैं। अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले निजी महाविद्यालय का शुल्क ढाँचा एक आम नागरिक के बच्चे की पहुंच से बहुत बाहर होता है। एक अंग्रेजी अखबार में छब्बीस अगस्त को छपी खबर के मुताबिक तमिलनाडु में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी संस्थानों का औसत शुल्क लगभग दो करोड़ तक पहुंच गया है। परास्नातक और अन्य प्रकार की चिकित्सा उपाधियाँ वाले पाठ्यक्रमों के शुल्क निजी महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में और भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। और हम जानते हैं कि एक आम आदमी का बच्चा दो करोड़ देकर डॉक्टर नहीं बन सकता। वर्तमान व्यवस्था ने चिकित्सा शिक्षा तंत्र को वह औपचारिक रूप दे डाला है जहां आर्थिक स्तर और वर्गीय विशेषाधिकारों के आधार पर विद्यार्थियों में भेद ऐदा हो गया है, श्रेणीकरण हो गया है। वैसे तो ऐसा स्तर भेद होना किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय है लेकिन भावी चिकित्सकों के बीच इस प्रकार का भेदभाव विलक्षुल स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा पेशा है जहां आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है। चिकित्सक में सहानुभूति, परोपकार और सेवाभाव की आम जनता बड़ी इज्जत करती है अत इन गुणों को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या निजी क्षेत्र से आप इन चीजों की उम्मीद कर सकते हैं? चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मची इस अंथी लूट और

तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का संज्ञान लेकर मई में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को हिदायत दी थी कि संसद की स्थायी समिति के सुझाव के अनुसार एक निगरानी समिति बनाई जाए जो भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यों पर निगरानी रख सके। यहां गैरतलब है कि देश में चिकित्सा शिक्षा के नियमन का काम यही परिषद देखती है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वयं यह संस्था आज निर्जीव और निष्प्रभ हो चुकी है। न तो भारतीय चिकित्सा परिषद देश भर में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के स्तर पर कोई गुणवत्तापूर्ण मानक निर्धारित कर पाई है और न ही इसने मैटिकल शिक्षा को सुलभ और सस्ता बनाने की दिशा में कोई मुकम्मल कदम ही कभी उठाया है। उलटे लोकहित के नाम पर निजी न्यासों और अन्य संस्थानों को चिकित्सा महाविद्यालय आदि खोलने का मौका देकर परिषद ने पहले ही चिकित्सा शिक्षा को आम आदमी की जेब से बाहर कर दिया है निजी क्षेत्र को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरने की छूट देने के पीछे तर्क दिया गया कि सरकारी महाविद्यालय उतनी संख्या में चिकित्सक तैयार नहीं कर सकते, जितनी जरूरत है। यह भी कहा गया कि प्रतिसर्पण बढ़ने पर निजी महाविद्यालयों के शुल्क स्वत ही कम हो जाएंगे। लेकिन आज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी महाविद्यालयों की संख्या लगभग पांच सौ तक पहुंच जाने पर भी क्या चिकित्सा पाठ्यक्रमों के शुल्कों में गिरावट आइ है? इसका जवाब ना में ही होगा। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जवाब तलब किए जाने पर सरकार के निर्देश पर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक का जो मसौदा सरकार को सौंपा है वह विवाद के घेरे में आ गया है।

जड़ धारणा



हर महीने दुनियाभर में लाखों
महिलाओं को माहवारी आने पर पेट
दर्द, बैचैनी, शर्म, चिंता और दयनीय
चक्र का सामना करना पड़ता है। आम
जनजीवन में यह हमेशा उन वर्जनाओं
और मिथकों से घिरा रहा है जो
महिलाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक
जीवन के कई पहलुओं से बाहर करता
है। भारत में आमतौर पर इस विषय पर
बात करना सहज नहीं माना जाता है।
आज भी इस विषय पर ज्ञान की उन्नति
के लिए सामाजिक प्रभाव एक बाधा
प्रतीत होता है। भारत के कई हिस्सों में
सांस्कृतिक रूप से माहवारी को गंदा
और अशुद्ध माना जाता है। इस दौर से
गुजरती महिलाओं और लड़कियों को
कई तरह के काम, रसोईघर और मटिरों
से दूर रखा जाता है। माहवारी के
असुरक्षित हालात कई बार महिलाओं

गर्भाशय के कैंसर की ओर धकेल हैं। देश में आज भी कुछ ऐसे महिलाएँ हैं, जहां पर मासिक धर्म वाली महिलाओं को नहाने की अनुमति नहीं दी जाती। जबकि यह गलत है। यों यह एक बहुत पुराना है, जो हमारे यहां कथाओं के जरिए जड़ पकड़ता रहा। इस धारणाओं ने इस प्राकृतिक चक्र महिलाओं के लिए एक शूलीफदेह दौर बना दिया है। जबकि ऐसे संबंधित जितने भी तथ्य सामने चुके हैं, उसकी सामान्य जानकारी महिलाओं के प्रति धारणा को बदल सकता है। लेकिन समाज में पसरी छठित और स्त्री विरोधी सोच ने नूमन हर बहाने से महिलाओं को दूर करके रखने का इंतजाम किया हालांकि महिलाओं की इस स्थिति खमियाजा समाज को ही भगतना पड़ा है, जिसमें उसका कोई विकास का चेहरा आईने में आधा-आधूरा दिखता है। शेयर बाजार की उठापटक से आज हर कोई असमंजस में है। अल्पकाल में ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच, निवेशकों को जोखिम लेने के लिए उत्साहित कर रहा है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के चलते स्थिति खराब है। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। संसेक्स व निफ्टी दोनों सूचकांक नीचे हैं। निवेशकों को समझाना होगा कि अच्छे मुनाफे की लिए दीर्घकालीन निवेश ही बेहतर विकल्प है। अनेक टीवी चैनलों पर निवेश के नुस्खे दिए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर कोरी कल्पना पर आधारित होते हैं। निवेशकों को अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना चाहिए, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सके।

सन्पादकीय

मालेगांव बम विस्फोट केस में 17 साल बाद बरी

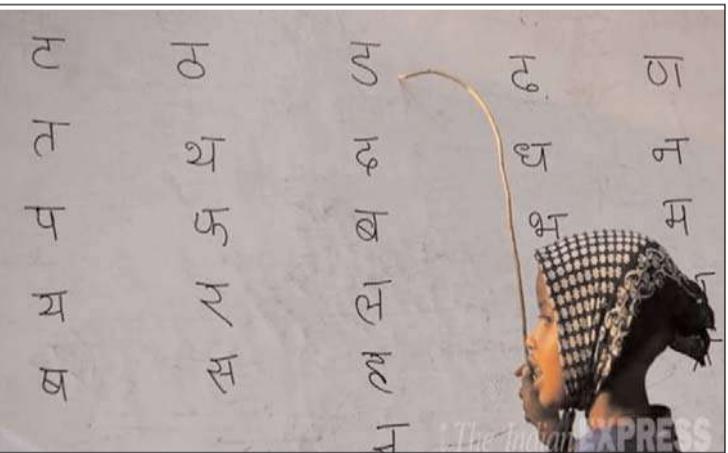


यह एक विचित्र विडंबना है कि आतंकवाद जैसे जटिल मसलों पर भी किसी खास घटना की जांच, उसकी समूची प्रक्रिया और उसके निष्कर्ष अदालत के कठघरे में ढह जाते हैं और वर्षों से जेल में बंद या फिर आतंकवाद के आरोपों में मुकदमा झेल रहे लोग बरी हो जाते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी मामले में कार्रवाई के क्रम में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर अदालत में मुकदमा चलाया जाए। भगव समूचे मामले की सुनवाई के बाद अगर सभी आरोपी बरी कर दिए जाएं, आरोप साबित करने के लिए पेश सबूतों पर सवाल उठें, तो यह किस तरह की कार्यप्रणाली का सबूत है? गौरतलब है कि पिछले सत्रह वर्षों से सुरियों में रहे मालेगांव बम विस्फोट के मामले में गुरुवार को मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने फैसला सुनाया और भजपा की पूर्व संसद सांख्यी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात लोगों को आरोपी से बरी कर दिया। सन 2008 में हुई उस घटना के संदर्भ में अदालत ने कहा कि केवल शक के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते। अदालत के इस फैसले से एक बार फिर कई सवाल उठे हैं। आतंकवादी वारदात जैसे किसी सबसे संवेदनशील मामले की पड़ताल करते हुए कोई एजेंसी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि आरोप और आरोपियों को लेकर उसकी मुख्य स्थापनाएं खारिज कर दी जाएं। मालेगांव बम विस्फोट से जुड़े मुकदमे में विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को निर्दोष करार देते हुए कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है, जिसमें आम नागरिक मारे गए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाया। हैरानी की बात है कि एक ओर जिन सबूतों के आधार पर यह मुकदमा सत्रह वर्षों तक चलता रहा, वे इतने निराधार थे कि सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया, दूसरी ओर उन सबूतों के गलत साबित होने में इतने वर्ष लग गए! इसी तरह, मुंबई में सन 2006 में सिलसिलेवार विस्फोटों के उन्नीस वर्ष के बाद हाई कोर्ट ने सभी बारह आरोपियों को बरी कर दिया। उस मामले में भी अदालत ने यही कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। मुंबई में ट्रेनों में सिलसिलेवार हुए बम विस्फोटों की घटना में तब एक सौ नवासी यात्रियों की जान चली गई थीं और आठ सौ चौबीस लोग घायल हो गए थे। सवाल है कि देश की शीर्ष जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और छानबीन का स्तर अगर यह है कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत बरी कर देती है, तो आखिर उतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले कौन थे और उन्हें नहीं पकड़ पाने के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि जो जांच एजेंसियां आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों में पूरी पड़ताल के बाद आरोपियों को कठघरे में खड़ा करती हैं, उनकी जांच अदालत में खामियों से भरी पाई जाती है, गवाहों के बयानों में विरोधाभास होते हैं, कई अपने बयान से मुकर जाते हैं और आखिर आरोपी बरी हो जाते हैं। इसके अलावा, एक ही मामले की जांच करते हुए अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंक निरोधक दस्ते के आरोपण में विरोधाभास होते हैं, तो यह किस तरह की कार्यप्रणाली और तालमेल को दर्शाता है?

बोली की मार

क्या हम कभी इस पर विचार करते हैं कि अपने विराध्यों के लिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल अखबारों में, समाचार चैनलों पर और सोशल मीडिया में किया जाता है, उसका समाज पर और खास कर बच्चों पर क्या दुष्परिणाम होगा? क्या अपने विरोधियों को धराशायी कर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना ही राजनीति का एक मात्र लक्ष्य रह गया है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा अब यह नया मानक रखेगी कि हमारे भीतर की लोकतांत्रिक भावनाएं और विचार को खत्म होना होगा?

ब चपन में हमें सिखाया गया था कि वाणी का एक पर्यायवाची शब्द 'सरस्वती' भी होता है। वैसे तो भारतीय संस्कृती की हिंदू परंपरा में किसी भी काम की शुरुआत 'गणेश' का नाम ले कर करने की परंपरा रही है। तुलसीदास अपने ग्रंथ 'रामचरितमानस' के आरंभ में वाणी यानी सरस्वती की आराधना गणेश से भी पहले करते हैं। इस काव्य के पहले श्लोक में तुलसीदास लिखते हैं- 'वंदे वाणीविनायकौं, यानी मैं सरस्वती और गणेश की बदना करता हूं। भाषा और सरस्वती का यह विनिमेय न केवल भारतीय संस्कृत में भाषा की महत्ता को रेखांकित करता है, बल्कि आज के चुनावी दौर में काफी प्रासांगिक है। यह छिपा नहीं है कि भाषा का स्तर चुनावी सरगर्मी के बीच गिरता जा रहा है और कोई भी राजनीतिक दल इससे अदूता नहीं है। जिस देश में आज से पांच सौ साल पहले से ही ऐसे ग्रंथों की रचना होती आई है, सामान्य व्यवहार में अक्सर 'मीठी वाणी' को बहुत महत्व दिया गया है, बोलने के लहजे को बेहतर या कमतर मनुष्य होने का रूपक माना गया, अक्सर दुश्मनों और नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए भी सम्मानपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहा हो, उसी देश के सार्वजनिक जीवन में भाषा का गिरता स्तर आखिरकार क्या दर्शाता है! ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरेलन ने अपने प्रसिद्ध आलेख 'पॉलिटिक्स एंड ड इंग्लिश लैंबेज़' (1946) में कहा था कि अंग्रेजी भाषा के गिरते स्तर का सीधा संबंध राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों में गिरावट से है। ऐसा लगता है कि हमारे राजनेताओं और बुद्धिजीवियों की नजर में इस तरह की बातों का कोई मूल्य नहीं है। क्या हम कभी इस पर विचार करते हैं कि अपने विरोधियों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अखबारों में, समाचार चैनलों पर और सोशल मीडिया में किया जाता है, उसका समाज पर और खास कर बच्चों पर क्या दुष्परिणाम होगा? क्या अपने विरोधियों का



हाराशायी कर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना ही राजनीति का एक मात्र लक्ष्य रह गया है? क्या हमारे यहां लोकतंत्र की परंपरा अब यह नया मानक रखेगी कि हमारे भीतर की लोकतंत्रिक भावनाएं और विचार को खत्म होना होगा? क्या हम सभ्यता के उस दौर में कदम रखने जा रहे हैं जहां अपने से भिन्न मत रखने वाले और कमज़ोर तबक्कों के लोगों के अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं होगी? ब्रिटिश पत्रकार और उपन्यासकार रॉबर्ट हैरिस के ऐतिहासिक उपन्यास 'डिक्टेटर' में प्राचीन रोम के प्रसिद्ध राजनेता और कुशल वक्ता सिसरो का कहना है कि राजनेता का प्रमुख लक्ष्य अपने देश की खुशी होनी चाहिए, न कि यश हासिल करने की लालसा। लेकिन जब किसी भी कीमत पर सत्ता, वैभव और धन पहली प्राथमिकता बन जाए तो भाषा और नैतिकता दोनों का पतन आश्चर्य की बात नहीं। आज के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भाषा के गिरते हुए स्तर को देखते हुए दिनकर को 'रेशमरथी' से ये पक्कियां बरबस याद आती हैं। इन पक्कियों में कर्ण कृष्ण से कहते हैं- 'वृद्धा है पूछना, था दोष किसका/ खुला पहले गरल का कोष किसका/ जहर अब तो सभी का खुल रहा है/ हलाहल से हलाहल धुल रहा है'। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में धर्म का उल्लंघन दोनों तरफ से हुआ था, ठीक उसी प्रकार किसी एक राजनेता या दल को भाषा के गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न जाने भाषा के स्तर पर हलाहल से हलाहल धोने की प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कब और कैसे आ गई और कब तक रहेगी? प्रश्न यह उठता है कि इस नैतिक पतन के परिणाम कितने दूरांगी होंगे? औरवेल ने यह भी कहा था कि अगर हमारे विचार हमारी भाषा को भ्रष्ट कर सकते हैं तो हमारी भाषा भी हमारे विचारों को भ्रष्ट कर सकती है। अपरिष्कृत विचार अपरिष्कृत भाषा की जननी है या इसके विपरीत अनैतिक भाषा अनैतिक विचार को जन्म देती है। यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। लेकिन इस बात पर कोई दो मत नहीं हो सकता कि हमें अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। सुभाषचंद्र बोस और महात्मा गांधी में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते थे। भाषा में गिरावट का एक प्रमुख कारण है हाल के दिनों में किंतु बढ़ने की संस्कृति में लगातार गिरावट। जब ज्ञान का स्रोत मानक किताबें न हो कर सोशल मीडिया के हल्के-फूलके के संवाद हो जाएं तो वाद-विवाद की संस्कृति का पतन तो अवश्यंभावी है।



मुश्किल में फंसी तृप्ति डिमरी की 'धड़क 2'

पिछे साल शिरदात चतुर्वेदी और तुषि डिमरी की फिल्म 'धड़क 2' की घोषणा की गई थी। फिल्म नवंबर 2024 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, बाद में इसे साल 2025 तक के लिए टाक दिया गया। इस बीच चर्चा थी कि यह फिल्म इस साल होली के त्यौहार के आस-पास रिलीज हो सकती है। होली तो नजदीक आ रही है, लेकिन फिल्म का प्रमोशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

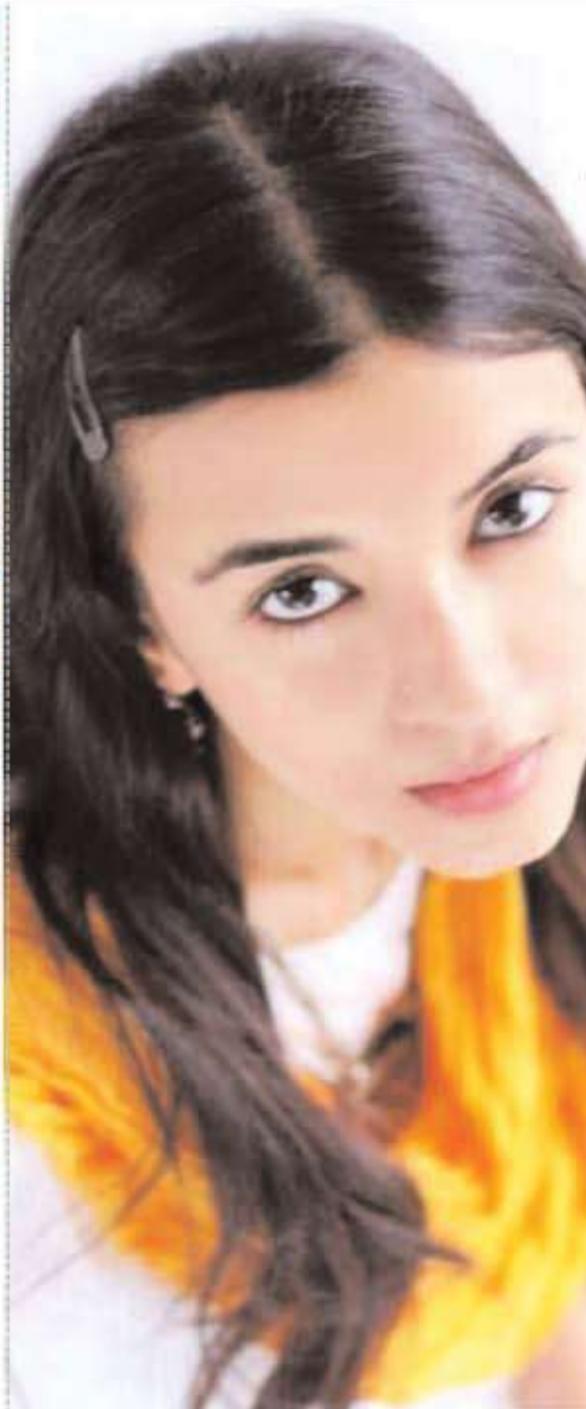
बॉलीवुड हाँगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'धड़क 2' की सीधीएफसी से प्रमाणन प्राप्त करने में तुम्हारियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से जिस समस्या का करना नहीं करना पड़ सकता है। बॉलीवुड हाँगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार पोर्टल को एक सूत ने बताया, धड़क 2 जाति के मुद्दों पर आधारित है और एक वौंगाने वाली कहानी है। सीधीएफसी की जाच समिति ने इस तरह की फिल्म के लिए निर्माताओं की सराहना की। इसके काटे की वजह से कह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि फिल्म को क्या रोटिंग दी जानी चाहिए और कौन से सीन काटे जाने चाहिए, यदि कोई ऐसा सीन हो।

संसर की मंजुरी के बाद शुरू होगा प्रमोशन?

रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रेड एक्सपर्ट ने पोर्टल को बताया कि 'धड़क 2' के निर्माता संसर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फिल्म का प्रमोशन शुरू करेंगे। इसलिए, अगर उन्हें सीधीएफसी से मंजुरी मिल जाती है, तो 'धड़क 2' 14 मार्च को रिलीज हो सकती है। इसके डेट की आगे बढ़ाया जा सकता है।

तमिल वर्जन पास तो 'धड़क 2' पर क्यों सवाल?

कहा जा रहा है कि 'धड़क 2' तमिल फिल्म 'परीयरुम पूरुषम' का रीमेक है और इस फिल्म की सीधीएफसी के साथ किसी भी मुरिकल का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि इसकी कहानी भी वही होगी तो किंवित इस फिल्म पर सवाल रखों उठ रहे हैं? साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'धड़क' भी इसी विषय पर आधारित थी। जाह्नवी कपूर और इशांत खट्टर की फिल्म मराठी फिल्म सेराट की रीमेक थी। फिल्म का गोइन्हा पोर्टर जब रिलीज हुआ था, तो उस पर लिखा था, एक था राजा, एक थी रानी। जात अलग थी खत्म कहानी। इससे अदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जातीय मुद्दों पर आधारित होगी।



तंडेल की सफलता के बाद डीजे बने नागा चैतन्य

नागा चैतन्य इन दिनों अपनी फिल्म तंडेल की सफलता का जश्न मना रहे हैं। अब नागा चैतन्य की एक यारी तर्वारी सोशल मीडिया पर व्हायरल हो रही है। शोभिता धुलियाल ने हाल ही में अपने इस्टर्नग्राम हैंडल पर एक महीने के लिए यारों ही और अपनी जिदीयों से निराश है। साथ ने आगे कहा कि उस इवान की फिल्म क्यों जो बिना नाम, बिना चेहरे का है और अपनी जिदीयों से निराश है। साथ ने आगे कहा कि उसे इसके साथ नहीं रह सकते न ही इसके बिना रह सकते हैं। जैसे-जैसे लोगों में असतीष बढ़ता है, वैसे-वैसे ऑनलाइन इस तरह का व्हायरल भी बढ़ता है।

नागा चैतन्य का सफलता सेटअप के साथ म्यूजिक मिक्सिंग में व्हायरल दिखे। स्वरकर के साथ केजुआल कपड़े पहने वह अपने गले में हेडफोन लटकाए डीजे की तरह ध्वनि को दिखा रहे थे। शोभिता ने तर्वारी साझा करते हुए चैतन्य को टैग किया और दिल वाल इवानी भी बनाए।



निजी जिंदगी पर ट्रोल करने वालों को सबा ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड की अभिनेत्री सबा आजाद अकसर त्रोल रोशन की गर्लफैंड होने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती है। हाल ही में उहाने रुकौन के दिए इन्होंने बुलाता है कि वह सोशल मीडिया पर असहज होती है। जब भी उहाने सोशल मीडिया पर कोई ट्रोल करता है, तो

वह इससे प्रभावित होती है। सोशल मीडिया से नहीं रह सकते दूर सबा आजाद ने कहा कि सोशल मीडिया थोड़ा अजीब है। उहाने कहा कि मैं लगातार तीन दिन तक पोस्ट करती हूँ और फिर एक महीने के लिए यारों ही जाती हूँ। यह कलाकारों के लिए एक तरह का पॉर्टफोलियो बन गया है। इससे ऐसे रास्ते साथ नहीं रह सकते न ही इसके बिना रह सकते हैं। जैसे-जैसे लोगों में असतीष बढ़ता है, वैसे-वैसे ऑनलाइन इस तरह का व्हायरल भी बढ़ता है।

चमड़ी मोटी हो गई है सबा ने आगे कहा कि अगर आप खुश इंसान हैं तो आए एक फेंक अकाउंट बनाकर किसी को ट्रोल नहीं करें। हम उस इवान की फिल्म क्यों जो बिना नाम, बिना चेहरे का है और अपनी जिदीयों से निराश है। साथ ने आगे कहा कि उन्होंने इवान ट्रोल किया गया है कि अब उनका बताया विनाराज होने के बावजूद दुखा रास्ता यह है कि इसे देखा जाए। मैं दुखी हूँ कि ट्रोलस को ये सब करना पड़ा रहा है। सबा ने आगे कहा कि जुलूआत में मैंने सोचा कि अगर मैं अपने काम पर ध्यान

दें रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन फिर, जब मैंने इस पर विचार किया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दुख है, और इसके लिए अपनी नीद उत्तर करना जरूरी नहीं है। लेकिन अब मेरी बमड़ी मोटी हो गई है। मैंने भले ही लंबे वक्त तक दूसरा गाल आगे कर रखा है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझमें अभी भी जवाब देने की ताकत है। अब आप नुसार से उमीदों नहीं का सफलता कि मैं खामोश रहूँ। मैंने परवाह नहीं कि अब लोग मुझे क्या कहेंगे। हाल ही में जब हूँ इन योर गाइनेक के दूधसे सीजन का शो रिलाज किया गया तब किसी ने कहा कि वह ज़ीरोक की गर्लफैंड हैं इन्हींने। अब काम करने की जरूरत नहीं है। इस पर सबा ने ट्रोलर को जवाब दिया था।

रिश्ते के बारे में सबा और ज़ीरोक रोशन ने साल 2022 में एक ट्रोल को डेटिंग करना शुरू किया। दोनों ने अपने रिश्ते का एलान अक्टूबर 2022 में किया। तब ज़ीरोक ने सबा के साथ तस्वीर शेयर की थी। तभी से सबा को ज़ीरोक की गर्लफैंड होने के लिए जो रहा है। हाल ही में सबा आजाद को क्राइम बीट में देखा गया। इस फिल्म में सबा के अलावा सुधीर मिश्र और संजीव कील हैं। इसमें सोकिंग सलीम, राहुल भट्ट के अलावा दानिश बत्तावाल की नीलंद व प्रासुद यू पर आधारित है। इसमें खाज़ी प्रकारिता और रिपोर्टिंग के बारे में दिखाया गया है।

बनना चाहिए 'पठान' का प्रीव्यूल बॉलीवुड रिपोर्टर को दिए गए एक इंटरव्यू में एक्टर ज़ीरोक ने कहा है, 'मैं किसी ईंचाइनी फिल्म का हिस्सा तभी बनता हूँ, जब उसमें मेरा किरदार खास होता है। जैसे फिल्म 'पठान' में जैम का किरदार नहीं किसी साक्षी को लेकर तो जैन खुश हैं। इस फिल्म की कहानी को लेकर तभी खास होता है।' अग्री वह कहते हैं, 'आदित्य चोपड़ा फिल्म 'पठान' का प्रीछाल भी बनाए। आदित्य चोपड़ा फिल्म में जैन ने असली फिल्म 'डिलीमेट' को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में जैन ने असली डिलीमेट रहे जैपी सिंह की कहानी पाकिस्तानी में फैली, भारत की एक बैटी को सुरक्षित रख वापस लाने की है। इस फिल्म को लेकर तो जैन खुश है। साथ ही वह चाहते हैं कि ग्रीड्यूर आधित्य चोपड़ा फिल्म 'पठान' का प्रीछाल भी बनाए।



करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने मार्को निर्देशक के साथ मिलाया हाथ, एक्शन फिल्म पर साथ करेंगे काम

ग्रन्थालय फिल्मों के एक्शन रेटर हाँगीफ अदेनी बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रहे हैं और वह इसे अपने स्टाइल में कर रहे हैं। मार्कों की भूमिका में धमाल मचाने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस ने एक धमाकेदार एक्शन फिल्म के लिए साइरन किया है, जो जिती दमदार है, उत्तीर्णी में धमदार भी है। द ग्रेट फारद 2019 पर मिलेन 2019 पर एक अदेनी ने एक बार फिर मार्कों के साथ अपना धमाकेदार एक्शन के लिए लैटर किया है। अब वह अपनी सिंहनेवर हाँगे-इंपैक्ट स्टोरीटेलिंग को हिंदी सिनेमा में लाने के लिए तैयार है। कथित तौर पर आगामी प्रोजेक्ट को बूब्हामी रिलायू के लिए लैन किया जा रहा है। फिल्म के बारे में विवरण अभी भी गुप्त रखा गया है।

आधिकारिक एलान का इन्तजार

हाँगीफ अदेनी के जुड़ने से धमाकेदार हैनर वह एक्शन की तरह ध्वनि को दिखा रहा है। दूसरी ओर इसके अधिकारिक एलान का इन्तजार है। साथ ही कलाकारों की धोणा होनी भी बाकी है। हाँगीफ अदेनी एक फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, जो मलायालम सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2017 की फिल्म द ग्रेट फारद से इन्हें जूनियर में कदम रखा था। प्रतकथा लेखक के रूप में उनका आगामी काम अमीर है, जिसमें मार्गी गुण्य भूमिका में है। धमाकेदार अब कई प्रोजेक्टों की रिलायू की तैयारी कर रहा है। जिसमें से एक है- केरारी चैप्टर 2, जो जलियावाला बाग हम्पाकांड की बाई घंटाओं पर आधारित है। यह फिल्म अक्षय कुमार, आर. मालवन और अनन्या पांडे स्टारर 2024 में रिलायू करेगी। इसके साथ ही, धड़क 2 भी है। इसके तौर पर रियायम पेरुमल पर आधारित एक शक्तिशाली लव ड्रामा है, जिसमें तुली डिमरी और सिद्धांत चुरुपेदी मुख्य भूमिका में हैं।

निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत के साथ अक्षय कुमार, रवीना टंडन, दिशा पटानी, सुनील शेटी, लाला दावा, बॉबी देओल, जैफलीन फिल्मीज, परेश रावल, अरशद वारी, राजपाल यादव, जौनी लीवर, श्रेयस तलपटे और तुषार कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा, संजय दत क

